श्री कन्हैयालाल दाँ० वैद्य : इस वर्ष में आयात की गई रुई की गांठों का औसत मूल्य क्या है ?

श्री नित्यानन्द कानूनगो : सारी जितनी आयात हुई हैं उनका मूल्य चाहते हैं ?

श्री कन्हैयालाल दाँ० वैद्य : जी हां ।

श्री नित्यानन्द कानूनगो : यह अर्थमेटिक की चीज है, अभी नहीं कह सकता ।

श्री कन्हैयालाल दाँ० वैद्य : विभिन्न देशों से आयात की जाने वाली रुई की मात्रा किस आधार पर सरकार निर्धारित करती है ?

श्री नित्यानन्द कानूनगो : हमारी जरूरत जितनी होती है, उसी आधार पर करते हैं ।

श्री कन्हैयालाल दाँ० वैद्य : भारतीय रुई की गांठ का प्रचलित मूल्य क्या है ?

श्री नित्यानन्द कानूनगो : रेशे की लम्बाई के अनुसार अलग अलग मूल्य हैं ।

श्री कन्हैयालाल दाँ० वैद्य : मैं रुई का चाहता हूं ।

श्री नित्यानन्द कानूनगो : वह बहुत किस्म की है ।

श्री कन्हैयालाल दाँ० वैद्य : हाइयस्ट क्वालिटी की रुई की एक गांठ की कीमत क्या है ?

श्री नित्यानन्द कानूनगो : हाइयस्ट क्वालिटी की इंडियन काटन ?

श्री कन्हैयालाल दाँ० वैद्य : जी हां ।

श्री नित्यानन्द कानूनगो : अभी नहीं कह सकता ।

(Interruptions.)

MR. CHAIRMAN: He says that you are carrying on private conversation in which the House is not interested.

SHRI KANHAIYALAL D. VAIDYA: I am entitled to ask.

काली मिर्च पर निर्यात शुल्क

*३५८. **श्री कन्हैयालाल दाँ० वैद्य (श्री कृष्णकान्त व्यास की ओर से)**: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काली मिर्च पर लगने वाले निर्यात शुल्क में क्या हाल ही में कोई परिवर्तन किया गया है ?

†[EXPORT DUTY ON PEPPER

*358. SHRI KANHAIYALAL D. VAIDYA (ON BEHALF OF SHRI KRISHNAKANT VYAS): Will the Minister for COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state whether any change has been made in the export duty on pepper recently?]

वाणिज्य मंत्री (श्री डी० पी० करमरकर) : निर्यात शुल्क का अन्तिम संशोधन ९ जनवरी, १९५५ को हुआ था । इस समय निर्यात शुल्क की दर माल के मूल्य के अनुसार १५ प्रतिशत है ।

†[THE MINISTER FOR COMMERCE (SHRI D. P. KARMARKAR): The last revision of export duty took place on the 9th January 1955 and the rate now in operation is 15 per cent. *ad valorem*.]

श्री कन्हैयालाल दाँ० वैद्य : चूंकि मध्य पूर्व के देश काली मिर्च के भारी आयातक देश हैं अतः उन देशों में काली मिर्च के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री डी० पी० करमरकर : कार्यवाही तो सभी तरह की चलती रहती है निर्यात को बढ़ाने के लिये । हमारे ट्रेड कांसलेट्स हैं इसके लिये । इसके अलावा हमारे व्यापारी जो कुछ पूछते हैं वह इंफार्मेशन उनको देते हैं और सब प्रकार की कार्यवाही होती है और सहायता देते हैं ।

श्री कन्हैयालाल दाँ० वैद्य : इसके बाद मुझे यह मंत्री जी से पूछना है कि क्या काली मिर्च के भाव घट गये हैं ?

†English translation.

श्री डी० पी० करमरकर : जी हां ।

श्री कन्हैयालाल वी० वैद्य : काली मिर्च पर जो शुल्क लगाया गया था वह क्या अब भी जारी हैं ?

श्री डी० पी० करमरकर : वही तो मैंने बताया कि १५ फीसदी जारी हैं ।

श्री कन्हैयालाल वी० वैद्य : क्या यह सच हैं कि इसी शुल्क के कारण काली मिर्च के भाव घटते जा रहे हैं ?

श्री डी० पी० करमरकर : मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आया । एक्सपोर्ट ड्यूटी होने से काली मिर्च के भाव कभी कभी बढ़ते हैं और घटते नहीं हैं । दुनिया में भाव घटते हैं तो उस वक्त हमें सोचना होता हैं कि उसको घटायें या बढ़ायें ।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : देश में तो काली मिर्च के भाव घट रहे हैं पर विदेश में तो घट नहीं रहे हैं ? वहां घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं ?

(कोई उत्तर नहीं)

MR. CHAIRMAN: Questions are over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

PREVENTION OF SOIL EROSION

*350. SHRI N. C. SEKHAR: Will the Minister for IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposals from Hosdrug Sub-Taluk (South Kanara District, Madras State) for preventing soil erosion on the banks of Kariankot river in Nileshwar Firka of that Sub-Taluk;

(b) if so, from whom and what are the proposals; and

(c) what action Government have taken thereon?

THE DEPUTY MINISTER FOR IRRIGATION AND POWER (SHRI J. S. L. HATHI): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

जम्मू और काश्मीर सरकार को दिये गये ऋण और अनुदान

२०८. **श्री कृष्णकान्त व्यास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जम्मू और काश्मीर सरकार को वर्ष १९५४-५५ में कुल कितना ऋण और अनुदान दिया हैं, विशेष रूप से निम्नलिखित मदों के लिये----

(१) १९५४-५५ में असैनिक प्रशासन की सहायता के लिये ;

(२) १९४७-४८ से लेकर अब तक काश्मीर के मामलों से सम्बद्ध विभाग के लिये ; और

(३) संयुक्त राष्ट्र में काश्मीर के मामले के लिये उसके पेश किये जाने से अब तक ; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में उस राज्य को कितनी राशि देने का विचार हैं ?

†[LOANS AND GRANTS GIVEN TO JAMMU AND KASHMIR GOVERNMENT

208. SHRI KRISHNAKANT VYAS: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the total amount of loans and grants given by Government to the Government of Jammu and Kashmir during the year 1954-55; and, in particular, for—

(i) the aid to the civil administration in 1954-55;

(ii) the section dealing with Kashmir affairs since 1947-48; and

†English translation.